भारत में क्रूज पर यात्रा बढ़ने के आसार

बेहतर मौके देखते हुए कोस्टा क्रूजेज की तीन साल बाद भारत में वापसी, कराएगी लक्षद्वीप की यात्रा

अनीश फडणीस

भारत में क्रूज यात्रियों की तादाद वित्त वर्ष 2024 में महामारी से पहले का स्तर पार कर सकती है। मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव जलोटा ने सोमवार को कहा कि यात्रियों की बढ़ती तादाद के अनुरूप ही टर्मिनलों के विकास तथा सीमा शुल्क और आव्रजन के मानक संचालन नियमों को आसान किया जाएगा। जलोटा ने कहा, 'उम्मीद करते हैं कि हमें अक्टूबर से मुंबई में 130-140 क्रूज जहाजों की आवाजाही संभालनी होगी। भारतीय बंदरगाहों से जाने वाले क्रूज जहाजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।'

वित्त वर्ष 2022-23 में, चेन्नई, कोच्चि, मेर्मुग्ण्वो, मुंबई, न्यू मंगलूर और विशाखापत्तनम के बंदरगाहों ने 348,000 से अधिक क्रूज यात्रियों का प्रबंधन किया। वित्त वर्ष 2019-20 में, भारतीय बंदरगाहों में यात्रियों की तादाद 470,000 से अधिक था।

देश में सबसे अधिक क्रूज जहाज यात्री मुंबई बंदरगाह पर दिखते हैं और यहां एक नया क्रूज टर्मिनल विकसित हो रहा है जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 के अंत या वर्ष 2024 के आरंभ में हो जाएगी। चेन्नई में एक यात्री टर्मिनल की शुरुआत इस महीने के आरंभ में हुई जहां से श्रीलंका के लिए क्रूज लॉन्च किया गया। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी में भी नए टर्मिनलों की योजना बनाई जा रही है।

सोमवार को कोस्टा क्रूजेज ने भी छुट्टियों के दौरान देश में भीतर की जाने वाली यात्रा में तेजी का संकेत देते हुए तीन साल बाद भारत लौटने की घोषणा की।

कोस्टा क्रूजेज का एक जहाज चार सीजन के लिए मुंबई के बंदरगाह पर रहा था जब तक कि महामारी ने वैश्विक यात्रा बाधित नहीं की थी। इतालवी क्रूज लाइन का जहाज कोस्टा सेरेना अब नवंबर-जनवरी के बीच घरेलू मार्गों पर नजर आएगा। इसमें गोवा, कोच्चि और लक्षद्वीप के लिए 2 से 5 दिनों की 23 यात्राएं शामिल हैं। लक्षद्वीप को पहली बार शामिल किया गया था।

केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और इटली के महावाणिज्य दूत अलेसांद्रो दी माची ने मुंबई में हुए लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

एक घरेलू बंदरगाह वह है जहां से एक क्रूज जहाज अपनी यात्रा शुरू या समाप्त करता है जो पारगमन स्थल से अलग होता है। परंपरागत रूप से भारतीय बंदरगाहों ने विदेशी क्रूज जहाजों के लिए सामानों की आपूर्ति करने वाली जगह के रूप में काम किया। कोस्टा क्रूजेज के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी रॉबर्टो अल्बर्टी ने कहा, 'महामारी के बाद क्रूज उद्योग के लिए भविष्य उज्ज्वल है। हम यूरोप और दक्षिण अमेरिका में वृद्धि देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत भी ऐसा ही करेगा।'

क्रूज यात्रियों की संख्या

वित्त वर्ष	यात्री
2020	474,999
2021	593
2022	1,52,617
2023	3,48,291

स्रोत– मुंबई पत्तन प्राधिकरण

केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और इटली के महावाणिज्य दूत अलेसांद्रो दी माची ने मुंबई में हुए लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया

क्रूज में यात्रा करने वालों की बढ़ रही है संख्या

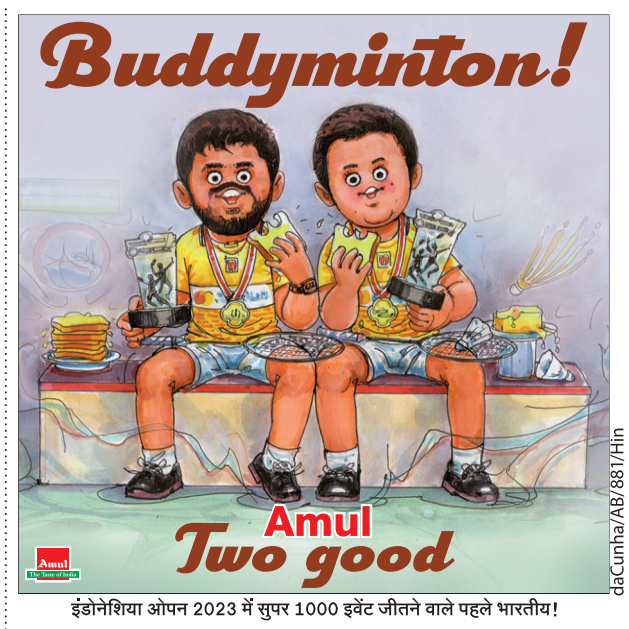

- वित्त वर्ष 2022-23 में, चेन्नई, कोच्चि, मेर्मुग्ण्वो, मुंबई, न्यू मंगलूर और विशाखापत्तनम के बंदरगाहों ने 348,000 से अधिक क्रूज यात्रियों का प्रबंधन किया
- वित्त वर्ष 2019-20 में, भारतीय बंदरगाहों में यात्रियों की तादाद 470,000 से अधिक थी
- देश में सबसे अधिक क्रूज यात्री मुंबई बंदरगाह पर हैं
- यहां एक नया क्रूज टर्मिनल विकसित हो रहा है जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 के अंत में हो जाएगी
- चेन्नई में एक यात्री टर्मिनल की शुरुआत इस महीने के आरंभ में हुई

इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 इवेंट जीतने वाले पहले भारतीय!

रवि सिन्हा रॉ प्रमुख नियुक्त किए गए

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी और पड़ोसी देशों के मामलों के विशेषज्ञ रवि सिन्हा को सोमवार को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सिन्हा, सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 30 जून, 2023 को पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी सिन्हा दो दशक से अधिक समय से इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी से जुड़े रहे हैं। वह वर्तमान में इस संगठन में दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी हैं। अपनी पदोन्नति से पहले वह रॉ की अभियानगत शाखा का नेतृत्व कर रहे थे। सिन्हा के ही बैच के अधिकारी तपन डेका खुफिया ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख हैं।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 59 वर्षीय सिन्हा की दो साल के कार्यकाल के लिए रॉ के सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सिन्हा को खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक को नियोजित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति करने का श्रेय दिया जाता है। अपनी नई भूमिका में, सिन्हा से आज के समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी और मानव खुफिया आयामों को एकीकृत करने की उम्मीद है।

दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के पूर्व छात्र सिन्हा ने कई क्षेत्रों में काम किया है और उनके पास अनुभव और ज्ञान का खजाना भी है। पड़ोसी देशों के मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले सिन्हा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक रूप से उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, कुछ देशों से सिख चरमपंथ को हवा देने की कोशिशें की जा रही हैं और पूर्वोत्तर में, खासकर मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास हो रहे हैं। सिन्हा ने पूर्व में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के अलावा कई देशों में काफी काम किया है।

सिन्हा के पूर्ववर्ती गोयल को जून 2019 में दो साल के लिए रॉ प्रमुख नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 2021 और जून 2022 में एक-एक साल का दो बार सेवा विस्तार दिया गया था। माना जाता है कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ गोयल ने पाकिस्तान के बालाकोट में फरवरी 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए की गई थी। पुलवामा हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक आत्मघाती हमलावर ने यह हमला किया था। हमले के जवाब में, भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी, 2019 को बालाकोट में जैश के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था। **भाषा**

दो साल के लिए नियुक्त किए गए

- सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे रवि सिन्हा
- सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं
- दो दशक से खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं सिन्हा
- वर्तमान में इस संगठन में दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी हैं

2,000 नोट वापसी से बढ़ेगी खपत

रिजर्व बैंक का 2,000 रुपये के नोट चलन से वापस लेने का फैसला चालू वित्त वर्ष में खपत को बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि दर को 6.5 प्रतिशत से भी आगे ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.1 प्रतिशत हो जाएगी और समूचे वित्त वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत वृद्धि का आरबीआई का अनुमान भी पीछे छूट सकता है।

एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, 'हम 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के प्रभावों की वजह से अप्रैल-जून तिमाही में वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद करते हैं। यह हमारे उस अनुमान की पुष्टि करता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि आरबीआई के अनुमान 6.5 प्रतिशत से अधिक रह सकती है।' आरबीआई ने जून महीने की शुरुआत में कहा था कि 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के आधे से अधिक नोट वापस आ चुके हैं। इनमें से 85 प्रतिशत नोट बैंकों में जमा के रूप में आए थे जबकि 15 प्रतिशत नोट बैंक काउंटरों पर अन्य मूल्य के नोट से बदले गए थे।

जीडीपी वृद्धि रह सकती है 6.5 प्रतिशत से अधिकः रिपोर्ट

एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2,000 रुपये के नोट के रूप में कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये प्रणाली में जमा के रूप में लौटेंगे। इनमें से करीब 92,000 करोड़ रुपये बचत खातों में जमा किए जाएंगे जिसका 60 प्रतिशत यानी करीब 55,000 करोड़ रुपये निकासी के बाद लोगों के पास खर्च के लिए पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, खपत में गुणक बढ़ोतरी की वजह से लंबे समय में यह कुल बढ़ोतरी 1.83 लाख करोड़ रुपये तक रह सकती है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नोट वापस लेने के आरबीआई के कदम से मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों को मिलने वाले दान में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और बुटीक फर्नीचर की खरीद को भी बढ़ावा मिलेगा। **भाषा**

आईआईटी मद्रास ने जुटाए 231 करोड़

यह रकम सीएसआर, फर्मों तथा पूर्व छात्रों, व्यक्तिगत दानदाताओं से मिली

आर्यमन गुप्ता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटी मद्रास) ने सोमवार को कहा कि उसे वित्त वर्ष 2022-23 में पूर्व छात्रों, उद्योग और अन्य दानदाताओं से 231 करोड़ रुपये मिले हैं, जो दान में मिली अभी तक की सबसे बड़ी राशि है। संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में उसे 131 करोड़ रुपये मिले थे यानी वित्त वर्ष 2023 में उसे 76 फीसदी ज्यादा रकम दान में मिली है। संस्थान के अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देने वालों की संख्या सालाना आधार पर 64 फीसदी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021 में आईआईटी मद्रास ने 101.2 करोड़ रुपये जुटाए थे। संस्थान ने कहा कि कुल मिलने वाली रकम 10 साल के दौरान 45 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है। यह रकम कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष तथा भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय फर्मों के अलावा संस्थान के पूर्व छात्रों, व्यक्तिगत दानदाताओं से मिली है।

आईआईटी मद्रास के ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट के मुख्य कार्याधिकारी कविराज नायर ने कहा, 'हमारे हितैषियों ने हमें स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, उर्जा, कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) और कृषि जैसे सामाजिक रूप से आवश्यक क्षेत्रों में नई तकनीकों के विकास के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने में मदद की। वे छात्रवृत्ति और फेलोशिप के माध्यम से जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। नायर ने कहा, 'पूर्व छात्रों ने कैंपस के समूचे बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे इनोवेशन हब, इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहायता की। इसके अलावा उन्होंने कैंपस में परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा। हम आईआईटी मद्रास से जुड़ा विश्वस्तरीय स्टार्टअप तंत्र बनाने के लिए अपने पूर्व छात्रों के साथ काम करते हैं।'

उन्होंने कहा कि पूर्व छात्रों के समर्थन से संस्थान को तकनीकी विशेषज्ञता, प्रोफेशनल नेटवर्क या वित्तीय संसाधनों में सहायता मिल सकती है। भारत भर में और विश्व स्तर पर पूर्व छात्रों और दानकर्ता व्यक्तियों ने संस्थान के लिए लगभग 96 करोड़ रुपये का योगदान दिया। विशेष क्षेत्रों में शोध के लिए चेयर प्रोफेसरशिप स्थापित करने के अलावा उनके फोकस क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक प्रभाव विषयों पर शोध, बुनियादी ढांचा और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं।

सीएसआर सेगमेंट में पिछले वर्ष की तुलना में 56 फीसदी की वृद्धि देखी गई, जिसमें पिछले वर्ष 40 की नई साझेदारी शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में दानकर्ताओं ने सबसे अधिक रुचि दिखाई उनमें सीएसआर के तहत अनुसंधान के लिए सहयोग है। वहीं ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रौद्योगिकी संचालित पहल पर भी दानकर्ताओं ने खासा जोर दिया है। 2023-24 के चालू वित्त वर्ष के लिए संस्थान के प्रमुख रकम जुटाने वाले लक्ष्यों में भारत और अमेरिका में पूर्व छात्रों की रकम जुटाने वाली टीम को मजबूत करना शामिल है ताकि पूर्व छात्रों के सेगमेंट में और अधिक पहुंच बनाई जा सके।

पूर्व छात्रों ने की भरपूर मदद

- वित्त वर्ष 2022 में 131 करोड़ रुपये मिले थे
- वित्त वर्ष 2021 में 101.2 करोड़ रुपये जुटाए थे
- संस्थान के अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देने वालों की संख्या सालाना आधार पर 64 फीसदी बढ़ी है

"पूर्व छात्रों ने कैंपस के बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे इनोवेशन हब, इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहायता की। उन्होंने कैंपस में परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा"
कविराज नायर,
मुख्य कार्याधिकारी

घरेलू सहायकों को मददगार की आस

काम पर रखने के बाद महीनों तक कामगारों को नहीं दिया जाता है वेतन

रक्षित कुमार और अनुष्का भारद्वाज

इस साल फरवरी की शुरुआत में अनिता श्याम (बदला हुआ नाम) को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके चेहरे पर चोट लगी थी और पूरे शरीर पर कटने और जलने के निशान थे। झारखंड की रहने वाली यह नाबालिग एक घर में काम करती थी और वहां उसके मालिक जो एक युवा जोड़ा था जिसने उसे प्रताड़ित किया था। महिला एक बड़ी जनसंपर्क कंपनी में काम करती थी और उसका पति एक बीमा कंपनी में कार्यरत था।

पुलिस की जांच में पता चला कि 17 वर्षीय श्याम को दिल्ली की किसी अपंजीकृत निजी एजेंसी से 30,000 रुपये जमा कर काम पर रखा गया था। उसे हर महीने 10,000 रुपये दिए जाने थे, लेकिन पिछले पांच महीने में दंपती ने उसे एक भी रुपया नहीं दिया।

इस घटना के तीन महीने बाद यानी 31 मई को फिर से एक घरेलू नौकर से जुड़ी एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। झारखंड के सिमडेगा से एक 15 वर्षीय किशोरी पिछले तीन महीने से लापता थी। उसका शव दिल्ली के राजौरी गार्ड के एक घर में लटका हुआ मिला था। शक था कि किसी अपंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी ने उसकी तस्करी की थी।

बंधुआ मजदूरी के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान समिति के राज्य संयोजक निर्मल गोराना इस मामले पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एजेंसी के पास कोई निबंधन संख्या नहीं थी और न संपर्क करने के लिए कोई व्यक्ति। उन्होंने कहा, 'कुछ दिनों तक तो एजेंसी ने नाबालिग की घर लौटने की गुहार तक नहीं मानी। उसकी आत्महत्या के बाद पुलिस ने हमसे कहा कि झारखंड में जाकर प्राथमिकी कराएं। पुलिस का अजीब तर्क था कि अपराध वहीं से शुरू हुआ था।'

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2021 में मानव तस्करी के 2,189 मामले दर्ज किए गए थे। यह साल 2020 से 27.7 फीसदी अधिक थे। तस्करी किए गए 6,533 पीड़ितों में से 2,877 नाबालिग थे।

घरेलू सहायकों के बाजार पर कोई नियम नहीं चलता है। इनके आधिकारिक आंकड़े विभिन्न पोर्टलों पर भिन्न रहते हैं। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में 47 लाख घरेलू कामगार थे। इस बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2011-12 ने इसे 39 लाख बताई थी। ई-श्रम पोर्टल पर जानकारी दी गई कि 30 जनवरी, 2023 भारत में 2.79 करोड़ घरेलू और सहायक कामगार हैं। इनमें से 2.67 करोड़ महिलाएं हैं।

अनौपचारिक अनुमानों से पता चलता है कि यह गणना सकल अनुमान से कम हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) दर्शाता है कि असल में यह संख्या 2 से 8 करोड़ के बीच हो सकती है।

गोराना कहते हैं, 'स्थानीय एजेंट विशेष रूप से 12 से लेकर 32 वर्ष तक की महिलाओं को अपंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसियों से जोड़ते हैं।' अधिकतर महिलाएं झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की होती हैं, जो नौकरी पाने से पहले दयनीय स्थिति में होती हैं। कार्यबल के प्रबंधन के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है।

इकनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके इन एजेंसियों के लिए भर्ती केंद्र होते हैं।

गोराना ट्रैकिंग सिस्टम की खामियों को दर्शाते हैं क्योंकि घरेलू कामगारों को अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 के तहत पंजीकृत नहीं किया जाता है। वह कहते हैं, 'चूंकि तस्करी किए गए लोगों को कहां से लाया गया है और कहां भेजा जा रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, इसलिए ऐसे लोगों का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है।'

भारत में चल रही ऐसे प्लेसमेंट एजेंसियों की संख्या का भी कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के कई प्रयासों के बाद भी किसी घर को कार्यस्थल के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

केवल 10 राज्यों ने ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत घर में काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य किया है। इनमें महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब शामिल है। हालांकि, यहां धरातल पर न्यूनतम मजदूरी कानून कितना प्रभावी है इसकी अलग कहानी है।

यहां तक की राष्ट्रीय राजधानी में जहां बड़ी संख्या में प्रवासी लोग घरेलू कामगार के रूप में काम करते हैं वहां भी प्लेसमेंट एजेंसियों की कोई सटीक संख्या ज्ञात नहीं है।

दिल्ली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी (विनियमन) आदेश, 2014 के तहत प्रदेश के श्रम विभाग को शहर में काम करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों को लाइसेंस देना जरूरी होता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि घरेलू सहायक मजदूरी नहीं मिलने पर, प्रताड़ित होने पर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में शिकायत कर सकते हैं।

न्यूनतम मजदूरी नियम का पालन कराने वाली दिल्ली की संस्था निर्मला निकेतन के संस्थापक सुभाष भटनागर ने कहा, 'श्रम विभाग प्लेसमेंट एजेंसियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है।'

भटनागर 2017 में निर्मला निकेतन के लिए लाइसेंस लेने की कोशिश के बारे में बताते हैं। वह याद करते हैं कि विभाग के अधिकारी इससे अनजान थे। उनके पास लाइसेंस जारी करने के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं थी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब से पता चलता है कि दिल्ली श्रम विभाग के पास इन एजेंसियों को जारी किए गए लाइसेंस का कोई आंकड़ा ही नहीं है। साल 2014 से विभाग ने 49 एजेंसियों पर जुर्माना लगाया है, जिनमें 41 एजेंसियों पर केवल साल 2021 में जुर्माना लगाया गया। डीसीडब्ल्यू को भेजे गए आरटीआई का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

घरों में काम करने वालों की स्थिति काफी भयावह है। राष्ट्रीय घरेलू कामगार आंदोलन की जिला संयोजक रेखा जाधव का कहना है कि प्लेसमेंट एजेंसियां न तो घर में काम करने वालों को उनके काम बताती हैं, न उन्हें रखने वालों के साथ कोई नियम तय करती है। वह कहती हैं, 'कई बार तो घर में काम करने वालों को बिना बताए गंभीर मरीजों के साथ छोड़ दिया जाता है।' एक बार काम पर रखाने के बाद उनके लिए काम छोड़ना बगैर किसी हेल्पलाइन नंबर के बहुत मुश्किल हो जाता है।

जाधव कहती हैं, 'एजेंसी और काम पर रखने वाले लोगों के बीच पैसे का लेनदेन किया जाता है, जिसके बारे में कामगारों को जानकारी नहीं होती है।'

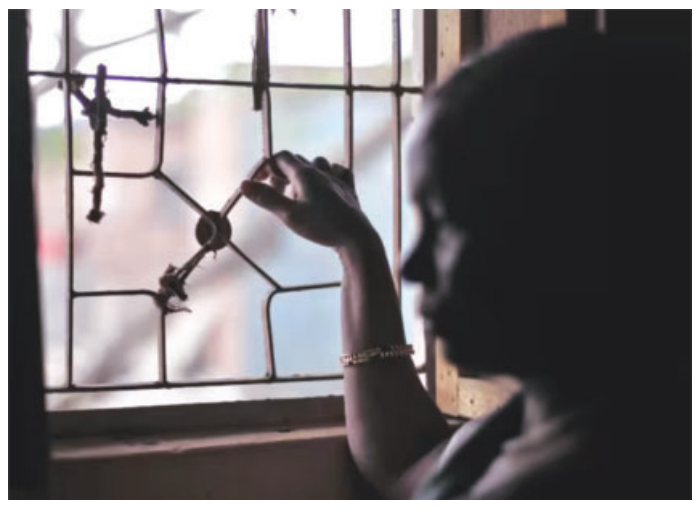

मालिकों से मारपीट और प्रताड़ना के शिकार भी होते हैं घरों में काम करने वाले

आज़ादी का अमृत महोत्सव
www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा 3 वर्षों के लिए डीसी, डीआरसी, एनडीआर में हार्डवेयर के वार्षिक रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट के नवीकरण और ऑन–साइट सपोर्ट हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है ।

इस संबंध में विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड में और सरकारी ई–मार्केटप्लेस **(GeM)** पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड में जारी किया जाएगा । प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई, 2023 है ।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 20.06.2023
मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)
49/23-24